After studying this chapter, the learners will

- figure out comparative trends in various economic and human development indicators of India and its neighbours, China and Pakistan
 - assess the strategies that these countries have adopted to reach their present state of development

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप

क भारत और इसके पड़ोसी देशों, चीन और पाकिस्तान के आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकों की तुलनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे;

ख विकास की वर्तमान अवस्था तक पहुँचने हेतु इन देशों द्वारा अपनाई गई उन नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे, जिन्हें इन देशों ने विकास की वर्तमान स्थिति तक पहुँचने के लिए अपनाया है।

INTRODUCTION

In the preceding units we studied the developmental experience of India in detail. We also studied the kind of policies India adopted, which had varying impacts in different sectors. Over the last two decades or so, the economic transformation that is taking place in different countries across the world, partly because of the process of globalisation, has both short as well as long-term implications for each country, including India.

परिचय

पिछली इकाइयों में हमने भारत के अनेक विकास अनुभवों का विस्तार से अध्ययन किया है। हमने यह भी अध्ययन किया था कि भारत ने किस प्रकार की नीतियां अपनाइं और उनके विभिन्न क्षेत्रकों पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े। पिछले लगभग दो दशकों से वैश्वीकरण ने विश्व के प्राय: सभी देशों में नवीन आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के कुछ अल्पकालिक, तो कुछ दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। भारत भी इनसे अछूता नहीं रहा है।

Nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. To this effect, they are forming regional and global economic groupings such as the SAARC, European Union, ASEAN, G-8, G-20, BRICS etc. In addition, there is also an increasing eagerness on the parts of various nations to try and understand the developmental processes pursued by their neighbouring nations as it allows them to better comprehend their strengths own and vis-à-vis their weaknesses neighbours.

विश्व के सभी राष्ट अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदढ़ करने के लिए अनेक उपाय अपनाते रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे अनेक प्रकार के क्षेत्रीय और वैश्विक सम्हों का निर्माण करते रहे हैं जैसे कि सार्क, य्रोपियन संघ, ब्रिक्स, आसियान, जी-8, जी-20 ब्रिक्स आदि। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राष्ट इस बात के लिए उत्सुक रहे हैं कि वे अपने पडोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। इससे उन्हें अपने पड़ोसी देशों की शक्तियों एवं कमजोरियों को बेहतर ने में मदद मिलेगी।

In the unfolding process of globalisation, this is particularly considered essential by developing countries as they face competition not only from developed nations but also amongst themselves in the relatively limited economic space enjoyed by the developing world. Besides, an understanding of the other economies in our neighbourhood is also required as all major common economic activities in the region impinge on overall human development in a shared environment

वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान इसे विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए आवश्यक समझा गया, क्योंकि वे अपेक्षाकृत सीमित स्थान में न केवल विकसित देशों द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे थे. बल्कि आपसी प्रतिस्पर्धा का भी। इसके अतिरिक्त, अपने पड़ोसी देशों की अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं की जानकारी भी आवश्यक थी. क्योंकि क्षेत्र की सभी मुख्य सामान्य आर्थिक गतिविधियां एक सहभागी वातावरण में मानव विकास से संबंधित थीं।

India and the largest two of its neighbouring economies— Pakistan and China. It has to be remembered that despite being endowed with vast natural resources, there is little similarity between the political power setup of India - the largest democracy of the world which is wedded to a secular and deeply liberal Constitution for more than half a century, and the militarist political power structure of Pakistan or the command economy of China that has only recently started moving towards a democratic system and more liberal economic restructuring respectively.

भारत और उसके दो बड़े पड़ोसी राष्ट्रों-पाकिस्तान और चीन द्वारा अपनाई गई विकासात्मक नीतियों की तुलना करेंगे। परंतु यह याद रखना होगा कि भौतिक साधन संपन्नता संबंधी समानताओं के बावजूद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और 50 से भी अधिक वर्षो से धर्मनिरपेक्षता और अति उदार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहे भारत की राजनीतिक शक्ति व्यवस्था और पाकिस्तान की सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीतिक शक्ति संरचना या चीन की निर्देशित अर्थव्यवस्था के बीच कोई समानता नहीं है। चीन ने तो हाल ही में उदारवादी व्यवस्था की दिशा में अग्रसर होना प्रारंभ किया है।

DEVELOPMENTAL PATH—A SNAPSHOT VIEW

Do you know that India, Pakistan and China have many similarities in their developmental strategies? All the three nations have started towards their developmental path at the same time. While India and Pakistan became independent nations in 1947, People's Republic of China was established in 1949. In a speech at that time, Jawaharlal Nehru had said, "These new and revolutionary changes in China and India, even though they differ in content, symbolise the new spirit of Asia and new vitality which is finding expression in the countries in Asia."

विकास पथ: एक चित्रांकन

क्या आप यह जानते हैं कि भारत. पाकिस्तान और चीन की विकासात्मक नीतियों में अनेक समानताएँ हैं। तीनों राष्ट्रों ने विकास पथ पर एक ही समय चलना प्रारंभ किया है। भारत और पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए जबिक चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरु ने अपने भाषण में कहा था ''यद्यपि भारत और चीन के बीच विचारधारा में बहुत भेद है, लेकिन नए और क्रांतिकारी परिवर्तन एशिया की नवीन भावना और नई शक्ति के प्रतीक हैं जो एशिया के देशों में साकार रूप ग्रहण कर रहे हैं।"

All three countries had started planning their development strategies in similar ways. While India announced its first Five Year Plan for 1951–56, Pakistan announced its first five year plan, now called the Medium Term Development Plan, in 1956. China announced its First Five Year Plan in 1953. Since 2013, Pakistan is working on the basis of 11th **Five Year Development Plan** (2013–18), whereas, China is now working on 13th Five Year Plan (2016–20).

तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी विकास नीतियां तैयार करना शुरू किया था। भारत ने 1951-56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की और पाकिस्तान ने 1956 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी, जिसे मध्यकालिक विकास योजना भी कहा जाता था। चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की। वर्ष 2013 में पाकिस्तान ने 11वीं पंचवर्षीय विकास योजना (2013-18) पर कार्य शुरू किया है जबकि चीन की तेरहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2016-20 है। भारत की वर्तमान योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 पर आधारित है।

Until March 2017, India has been following Five Year Plan- based development model. India and Pakistan adopted similar strategies, such as creating a large public sector and raising public expenditure on social development. Till the 1980s, all the three countries had similar growth rates and per capita incomes. Where do they stand today in comparison to one another?

मार्च 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित विकास नीति अपनाई जाती थी। भारत और पाकिस्तान ने समान नीतियां अपनाइं जैसे, वृहत् सार्वजनिक क्षेत्रक का सूजन और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय। 1980 के दशक तक तीनों देशों की संवृद्धि दर और प्रतिव्यक्ति आय समान थी। एक दूसरे की तुलना में आज उनकी स्थिति क्या है?

Before we answer this question, let us trace the historical path of developmental policies in China and Pakistan. After studying the last three units, we already know what policies India has been adopting since its Independence.

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आइए, हम चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों के एतिहासिक पथ की जानकारी लें। पिछली तीन इकाइयों का अध्ययन करने के बाद हम अब यह जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से कौन-सी नीतियां अपनाता रहा है।

China: After the establishment of People's Republic of China under oneparty rule, all critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under government control.

चीन: एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रकों, उद्यमों तथा भूमि, जिनका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, को सरकारी नियंत्रण में लाया गया।

The Great Leap Forward (GLF) campaign initiated in 1958 aimed at industrialising the country on a massive scale. People were encouraged to set up industries in their backyards. In rural areas, communes were started. **Under the Commune** system, people collectively cultivated lands. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population.

1958 में 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' अभियान श्रूक किया गया था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगीकरण करना था। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किये गये। कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 'कम्यून' 'थे जिनमें प्राय: समस्त कृषक शामिल थे।

GLF campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China killing about 30 million people. When Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialisation process. In 1965, Mao introduced the Great **Proletarian Cultural Revolution** (1966–76) under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside.

जी.एल.एफ. अभियान में अनेक समस्याएँ आयीं। भयंकर सुखे ने चीन में तबाही मचा दी जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग मारे गये। जब रूस और चीन के बीच संघर्ष हुआ, तब रूस ने अपने विशेषज्ञों को वापस बुला लिया, जिन्हें औद्योगीकीकरण प्रकिया के दौरान सहायता करने के लिए चीन भेजा गया था। 1965 में माओ ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया (1966-76)। छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और अध्ययन करने के लिए भेजा गया।

The present day fast industrial growth in China can be traced back to the reforms introduced in 1978. China introduced reforms in phases. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade and investment sectors. In agriculture, for instance, commune lands were divided into small plots, which were allocated (for use not ownership) to individual households

संप्रति चीन में जो तेज औद्योगिक संवृद्धि हो रही है, उसकी जड़ें 1978 में लागू किये गये सुधारों में खोजी जा सकती है । चीन में सुधार चरणों में शुरू किया गया। प्रारंभिक चरण में कृषि, विदेशी व्यापार तथा निवेश क्षेत्रकों में सुधार किये गये। उदाहरण के लिए, कृषि, क्षेत्रक में कम्यून भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में बाँट दिया गया जिन्हें अलग-अलग परिवारों को आवंटित किया गया (प्रयोग के लिये न कि स्वामित्व के लिए)।

They were allowed to keep all income from the land after paying stipulated taxes. In the later phase, reforms were initiated in the industrial sector. Private sector firms, in general, and township and village enterprises, i.e., those enterprises which were owned and operated by local collectives, in particular, were allowed to produce goods. At this stage, enterprises owned by government (known as State Owned Enterprises—SOEs), which we, in India, call public sector enterprises, were made to face competition

वे प्रकल्पित कर देने के बाद भूमि से होने वाली समस्त आय को अपने पास रख सकते थे। बाद के चरण में औद्योगिक क्षेत्र में सुधार आरंभ किये गये। सामान्य, नगरीय तथा ग्रामीण उद्यमों की निजी क्षेत्रक की उन फमों को वस्तुएँ उत्पादित करने की अनुमति थी, जो स्थानीय लोगों के स्वामित्व और संचालन के अधीन थे। इस अवस्था में उद्यमों को जिन पर सरकार का स्वामित्व था. (जिन्हें राज्य के उद्यम एस.ओ.ई. के नाम से जाना जाता है) और जिन्हें हम भारत में सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यम कहते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

The reform process also involved dual pricing. This means fixing the prices in two ways; farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government and the rest were purchased and sold at market prices. Over the years, as production increased, the proportion of goods or inputs transacted in the market also increased. In order to attract foreign investors, special economic zones were set up.

सुधार प्रक्रिया में दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति लागू थी। इसका अर्थ यह है कि कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता था। किसानों और औद्योगिक इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमतों के आधार पर आगतों एवं निर्गतों की निर्धारित मात्राएँ खरीदेंगे और बेचेंगे और शेष वस्तुएँ बाजार कीमतों पर खरीदी और बेची जाती थीं। गत वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ बाजार में बेची और खरीदी गई वस्तुओं या आगतों के अनुपात में भी वृद्धि हुई। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किये गये।

Pakistan: While looking at various economic policies that Pakistan adopted, you will notice many similarities with India. Pakistan also follows the mixed economy model with co-existence of public and private sectors. In the late 1950s and 1960s, Pakistan introduced a variety of regulated policy framework (for import substitution-based industrialisation).

पाकिस्तान: द्वारा अपनायी गई विभिन्न आर्थिक नीतियों पर विचार करते हुए आप यह देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक समानताएँ हैं। पाकिस्तान में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रकों के सह-अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अनुसरण किया जाता है। 1950 और 1960 के दशकों के अंत में पाकिस्तान के अनेक प्रकार की नियंत्रित नीतियों का प्रारूप लागू किया गया (उद्योगों पर आधारित आयात प्रतिस्थापन)।

Revolution led to mechanisation य्ग श्रूक हुआ और चुनिंदा क्षेत्रों की and increase in public investment आधारिक संरचना में सरकारी निवेश में in infrastructure in select areas, कृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप खाद्यानों which finally led to a rise in the production of foodgrains. This changed the agrarian structure इसके कारण कृषि भूमि संबंधी संरचना dramatically. In the 1970s, में भी नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ। nationalisation of capital goods 1970 के दशक में पूँजीगत वस्तुओं के industries took place. Pakistan उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके then shifted its policy orientation in बाद, पाकिस्तान ने 1970 और 1980 के the late 1970s and 1980s when the major thrust areas were denationalisation and encouragement of private sector.

The introduction of Green हरित क्रांति के आने से यंत्रीकरण का दशकों के अंत में अपनी नीति उस समय बदल दी, जब अ-राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जा रहा था और निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित किया जा रहा था।

During this period, Pakistan also received financial support from western nations and remittances from continuously increasing outflow of emigrants to the Middle-east. This helped the country in stimulating economic growth. The then government also offered incentives to the private sector

इस अवधि के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और मध्य-पूर्व देशों को जाने वाले प्रवासियों से निरंतर पैसा मिला। इससे देश की आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन मिला। तत्कालीन सरकार ने निजी क्षेत्रक को और भी प्रोत्साहन प्रदान किये।

Having studied a brief outline of the developmental strategies of China and Pakistan, let us now compare some of the developmental indicators of India, China and Pakistan.

चीन और पाकिस्तान की विकास नीतियों की संक्षिप्त रूपरेखा का अध्ययन करने के बाद, आइए अब हम भारत, चीन और पाकिस्तान के कुछ विकास संकेतकों की तुलना करें।

DEMOGRAPHIC INDICATORS

If we look at the global population, out of every six persons living in this world, one is an Indian and another a Chinese. We shall compare some demographic indicators of India, China and Pakistan. The population of Pakistan is very small and accounts for roughly about one-tenth of China or India.

जनांकिकीय संकेतक

यदि हम विश्व की जनसंख्या पर विचार करें तो पायेंगे कि इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक छ: व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतीय है और दूसरा चीनी। हम भारत में कुछ जनांकिकीय संकेतकों की तुलना करेंगे। पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह चीन या भारत की जनसंख्या का लगभग दसवां भाग है।

Though China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the three nations, its density is the lowest shows the population growth as being the highest in Pakistan, followed by India and China. Scholars point out the onechild norm introduced in China in the late 1970s as the major reason for low population growth.

यद्यपि इन तीनों में चीन सबसे बड़ा राष्ट है तथापि इसका जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है और भौगोलिक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। पाकिस्तान में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है, उसके बाद भारत और चीन का स्थान है। विद्वानों का मत है कि चीन में जनसंख्या की कम वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि 1970 के दशक के अंत में चीन में केवल एक संतान नीति लागू की गई थी।

They also state that this measure led to a decline in the sex ratio, the proportion of females per 1000 males. However, from the table, you will notice that the sex ratio is low and biased against females in all three countries. Scholars cite son preference prevailing in all these countries as the reason.

उनका यह भी कहना है कि इसके कारण लिंगानुपात (प्रत्येक एक हजार पुरुषों में महिलाओं का अनुपात) में गिरावट आई। परंतु सारणी से आपको पता चलेगा कि तीनों देशों में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में कम था और पूर्वाग्रह से युक्त था।

In recent times, all three countries are adopting various measures to improve the situation. Onechild norm and the resultant arrest in the growth of population also have other implications. For instance, after a few decades, in China, there will be more elderly people in proportion to young people. This led China to allow couples to have two children

आजकल तीनों देश स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। एक-संतान ोति और उसे लागू किये जाने के परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि थमने के अन्य प्रभाव भी थे। उदाहरण के लिए, कुछ दशकों के बाद चीन में वयोवृद्ध लोगों की जनसंख्या का अनुपात युवा लोगों की अपेक्षा अधिक होगा। इसके कारण. चीन को प्रत्येक दंपति को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति देनी पडी।

The fertility rate is also low in China and very high in Pakistan. Urbanisation is high in China with India having 34 per cent of its people living in urban areas

चीन में प्रजनन दर भी बहुत कम है और पाकिस्तान में बहुत अधिक। चीन में नगरीकरण अधिक है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में 34 प्रतिशत लोग रहते हैं।

GROSS DOMESTIC PRODUCT AND SECTORS

One of the much-talked issues around the world about China is its growth of **Gross Domestic Product.** China has the second largest GDP (PPP) of \$22.5 trillion in the world, whereas, India's GDP (PPP) is \$9.03 trillion and Pakistan's GDP is \$ 0.94 trillion, roughly about 11 per cent of India's GDP. India's GDP is about 41 per cent of China's GDP.

सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक चीन के बारे में विश्व में बहुचर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है। चीन का सकल घरेलू उत्पाद 22.5 ट्रीलियन विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत का स.घ. उत्पाद 9.3 ट्रीलियन तथा पाकिस्तान का जी,डी,पी, 1,1 ट्रिलियन डॉलर भारत के जी.डी. पी. के लगभग 11 प्रतिशत है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 41 प्रतिशत है।

When many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5 per cent, China was able to maintain near doubledigit growth during 1980s . Also, notice that in the 1980s, Pakistan was ahead of India; China was having double-digit growth and India was at the bottom

जब अनेक विकसित देश 5 प्रतिशत तक की संवृद्धि दर बनाये रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे तब चीन एक एसा देश था जो 1980 के दौरान से भी अधिक लगभग इसकी दोगुनी संवृद्धि बनाये रखने में समर्थ था। यह भी देखिए कि 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था। चीन की संवृद्धि दोहरे अंकों में थी और भारत सबसे नीचे था।

In 2015–17, there has been a decline in **Pakistan and China's** growth rates, whereas, India met with moderate increase in growth rates. Some scholars hold the reform processes introduced in Pakistan and political instability over a long period as reasons behind the declining growth rate in **Pakistan**

2015-2017 के दशक में पाकिस्तान और चीन की संवृद्धि दरों में मामूली गिरावट आई, जबिक भारत में विकास दर में मामूली वृद्धि कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान में 1988 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया तथा राजनीतिक अस्थिरता इस लंबी अवधि में प्रवृत्ति का मुख्य कारण था।

First, look at how people engaged in different sectors contribute to the **Gross Domestic Product** now called as Gross Value Added. It was pointed out in the previous section that China and Pakistan have more proportion of urban population than India

सबसे पहले यह देखें कि विभिन्न क्षेत्रकों में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद (जिसे अब सकल वधित मूल्य कहा जाता है) में योगदान कैसे करते हैं। पिछले खंड में बताया गया था कि चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है।

In China, due to topographic and climatic conditions, the area suitable for cultivation is relatively small — only about 10 per cent of its total land area. The total cultivable area in China accounts for 40 per cent of the cultivable area in India. Until the 1980s, more than 80 per cent of the people in China were dependent on farming as their sole source of livelihood. In 2018–19, with 26 per cent of its workforce engaged in agriculture, its contribution to the GVA in China is 7 per cent

चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कम अर्थात् कुल भूमि क्षेत्र का लगभग दस प्रतिशत है। चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 40 प्रतिशत है। 1980 के दशक तक चीन मे 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। 2018-19 में 27 प्रतिशत श्रमिकों के साथ कृषि ने चीन में सकल विधित मूल्य में 7 प्रतिशत में योगदान दिया

In both India and Pakistan, the contribution of agriculture to GVA were 16 and 24 per cent, respectively, but the proportion of workforce that works in this sector is more in India

भारत और पाकिस्तान में जी.डी. पी के लिए कृषि का योगदान 16 तथा 24 प्रतिशत था। परंतु इस क्षेत्रक में श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक है।

In Pakistan, about 41 per cent of people work in agriculture, whereas, in India, it is 43 per cent. Twenty four per cent of Pakistan workforce is engaged in industry but it produces 19 per cent of **GVA.** In India, industry workforce account for 25 per cent but produces goods worth 30 per cent of GVA.

पाकिस्तान में लगभग 41 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं: जबकि भारत में 43 प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगार में क्षेत्रकवार हिस्सेदारी भी यह दर्शाती है कि पाकिस्तान की चौबीस प्रतिशत श्रमशक्ति उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है जो कि सकल वधित मुल्य का केवल 19 प्रतिशत उत्पादन के बराबर है। भारत में उद्योग श्रमशक्ति 25 प्रतिशत है तथा सकल विधित मूल्य (ळटा) 30 प्रतिशत के बराबर माल का उत्पादन करते हैं।

In China, industries contribute to GVA at 41, and employ 28 per cent of workforce. In all the three countries, service sector contributes highest share of GVA.

चीन में उद्योगों का सकल विधित मूल्य 41 प्रतिशत योगदान है। जबिक 28 प्रतिशत श्रमशक्ति ही उद्योग क्षेत्र में कार्यरत है। इन तीनों ही देशों में सेवा क्षेत्र का सकल विधित मूल्य में योगदान सबसे अधिक है।

In the normal course of development, countries first shift their employment and output from agriculture to Industry and then to services. The proportion of workforce engaged in industry in India and Pakistan were low at 25 per cent and 24 per cent respectively. The contribution of industries to GVA is at 30 per cent in India and 19 per cent in Pakistan. In these countries, the shift is taking place directly to the service sector.

विकास की सामान्य प्रकिया के दौरान इन देशों ने सबसे पहले रोजगार और कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्हें विनिर्माण और उसके बाद सेवाओं की ओर परिवर्तित कर दिया। भारत और पाकिस्तान में विनिर्माण में लगे श्रमबल का अनुपात बहुत कम अर्थात क्रमश: 25 प्रतिशत और 24 प्रतिशत था। जी. बी.ए. में उद्योगों का योगदान भारत में 30 प्रतिशत और पाकिस्तान में 19 प्रतिशत है, जिससे यहां सीधे सेवा क्षेत्रक पर जोर दिया जा रहा है।

Thus, in all the three countries the service sector is emerging as a major player of development. It contributes more to GVA and, at the same time, emerges as a prospective employer. If we look at the proportion of workforce in the 1980s, Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector than India and China

इस प्रकार तीनों देशों में सेवा क्षेत्रक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है। यह जी.वी.ए. में अधिक योगदान कर रहा है और साथ ही यह संभावित नियोक्ता बन रहा है। 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि पाकिस्तान. भारत और चीन के अपेक्षा सेवा क्षेत्रक में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है।

In the 1980s, India, China and Pakistan employed 17, 12 and 27 per cent of its workforce in the service sector respectively. In 2019, it has reached the level of 32, 46 and 35 per cent, respectively

1980 के दशक में भारत, चीन तथा पाकिस्तान में सेवा क्षेत्रक में क्रमश: 17, 12, और 27 प्रतिशत श्रमबल कार्यरत था। वर्ष 2019 में यह बढ़कर 32, 46 और 35 प्रतिशत हो गया है।

In the last five decades, the growth of agriculture sector, which employs the largest proportion of workforce in all the three countries, has declined. In the industrial sector, China has maintained a near double-digit growth rate in 1980s but began showing decline in recent years, whereas, for India and Pakistan growth rate has declined.

पिछले पाँच दशकों में तीनों ही देशों में कृषि क्षेत्रक, जिसमें उक्त तीनों देशों के श्रमबल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था, की संवृद्धि में कमी आई है। चीन में तो (1980 के दशक में) द्विअंकीय संवृद्धि दर बनी रही. लेकिन हाल के वर्षों में गिरावट के संकेत हैं। किंतु भारत और पाकिस्तान में इसमें गिरावट आई है।

In case of service sector, China was able to maintain its rate of growth during 1980-1990, while there was a positive and increaring growth of India's service sector output. Thus, China's growth is contributed by the manufacturing and service sectors and India's growth by the service sector. During this period, Pakistan has shown deceleration in all three sectors.

1980-1990 के दौरान इसकी वृद्धि दर भारत के सेवा क्षेत्र के उत्पादन की सकारात्मक और बढ़ती हुई वृद्धि थी। इस प्रकार, चीन की आर्थिक संवृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण और सेवा क्षेत्रकों और भारत की संवृद्धि सेवा क्षेत्रक से हुई है। पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रकों में गिरावट आई है।

INDICATORS OF HUMAN DEVELOPMENT

You might have studied about the importance of human development indicators in the lower classes and the position of many developed and developing countries. Let us look how India, China and Pakistan have performed in some of the select indicators of human development.

मानव विकास के संकेतक

आपने निचली कक्षाओं में मानव विकास के संकेतकों के महत्व और अनेक विकसित और विकासशील देशों की स्थिति के विषय में पढ़ा होगा। आइए, हम देखें कि भारत, चीन और पाकिस्तान ने मानव विकास के चुनिंदा संकेतकों में कैसा निष्पादन हुआ है

China is moving ahead of India and Pakistan. This is true for many indicators income indicator such as GDP per capita, proportion of population below poverty line or health indicators such as mortality rates, access to sanitation, literacy, life expectancy or malnourishment. Pakistan is ahead of India in reducing proportion of people below the poverty line and also its performance in sanitation.

चीन भारत तथा पाकिस्तान से आगे है। यह बात अनेक संकेतकों के विषय में सही है जैसे. आय संकेतक अर्थात प्रतिव्यक्ति जी.डी.पी अथवा निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या का अनुपात अथवा स्वास्थ्य संकेतकों जैसे कि मृत्यु दर, स्वच्छता, साक्षरता तक पहुँच, जीवन प्रत्याशा अथवा कुपोषण। पाकिस्तान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात कम करने में भारत से आगे है। स्वच्छता के मामलों में इसका निष्पादन भारत से बेहतर है।

But neither of these two countries have been able to save women from maternal mortality. In China, for one lakh births, only 27 women die whereas in India and Pakistan, about 178 and 174 die respectively. women the all three Surprisingly countries report providing improved drinking water sources for most of its population. You will notice that for the proportion of people below the international poverty rate of \$ 3.20 a day, India has the largest share of poor among the three countries.

किंतु ये दोनों देश महिलाओं को मातृमृत्यु से बचा पाने में असफल रहे हैं। चीन में प्रति एक लाख जन्म पर केवल 27 महिलाओं की मृत्यु होती है. जबिक भारत और पाकिस्तान में यह संख्या 178 एवं 174 ऊपर है। आश्चर्य की बात यह है कि तीनों देश उत्तम पेय जल स्रोत उपलब्ध करा रहे हैं। आप यह भी देखेंगे कि 3.20 डॉलर प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता दर के नीचे के लोगों का अनुपात भारत में तीनों देशों से अधिक गरीब व्यक्ति है।

'liberty indicators' like measures of 'the extent of Constitutional protection given to rights of citizens' or 'the extent of constitutional protection of the Independence of the **Judiciary and the Rule of** Law' have not even been introduced so far. Without including these (and perhaps some more) and giving them overriding importance in the list, the construction of a human development index may be said to be incomplete and its usefulness limited.

स्वतंत्रता संकेतक इनमें अभी तक नहीं जोड़े गये हैं जैसे, नागरिक अधिकारों की संवैधानिक संरक्षण की सीमा. न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सरंक्षण देने की संवैधानिक सीमा तथा विधि-सम्मत शासन अभी तक लाग् नहीं किया गया है। इन्हें और कुछ उपायों को सूची में शामिल किये बिना तथा इन्हें महत्व दिये बिना, मानव विकास सूचक का निर्माण अधूरा रहेगा तथा इसकी उपादेयता भी सीमित होगी।

DEVELOPMENT STRATEGIES - AN APPRAISAL

It is common to find developmental strategies of a country as a model to others for lessons and guidance for their own development. It is particularly evident after the introduction of the reform process in different parts of the world. In order to learn from economic performance of our neighbouring countries, it is necessary to have an understanding of the roots of their successes and failures

विकास नीतियां: एक मूल्यांकन

सामान्यतया यह देखा जाता है कि किसी देश की विकास नीतियों को अपने देश के विकास के लिए मार्गदर्शन एवं सीख के रूप में ग्रहण किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में सुधार कार्यक्रमों के लागू होने के पश्चात. एसा विशेष रूप से देखा जा सकता है। अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक सफलताओं से कुछ सीख ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी सफलताओं तथा विफलताओं के मूल कारणों को समझ।

Though countries go through their development phases differently, let us take the initiation of reforms as a point of reference. We know that reforms were initiated in China in 1978, Pakistan in 1988 and India in 1991. Let us briefly assess their achievements and failures in pre- and post-reform periods.

विभिन्न देश अपनी विकास प्रक्रिया अलग-अलग तरीकों से पूरा करते हैं। आइए, सुधार कार्यक्रमों के आरंभ को हम संदर्भ बिंदु के रूप में लें। हम जानते हैं कि सुधार कार्यक्रम का आरंभ चीन में 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में हुआ। आइए, सुधार पूर्व और सुधार पश्चात् अवधि में उनकी उपलब्धियों और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन करें।

Why did China introduce structural reforms in 1978? China did not have any compulsion to introduce reforms as dictated by the World Bank and International Monetary Fund to India and Pakistan. The new leadership at that time in China was not happy with the slow pace of growth and lack of modernisation in the Chinese economy under the Maoist rule

ंचीन ने संरचनात्मक सुधारों को 1978 में क्यों प्रारंभ किया? चीन को इन्हें प्रारंभ करने के लिए विश्व बैंक और अतंर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की कोई बाध्यता नहीं थी जैसी कि भारत और पाकिस्तान को थी। चीन के तत्कालीन नये नेता माओवादी शासन के दौरान चीन की धीमी आर्थिक संवृद्धि और देश में आधुनिकीकरण के अभाव को लेकर संतुष्ट नहीं थे।

They felt that Maoist vision of economic development based on decentralisation, self sufficiency and shunning of foreign technology, goods and capital had failed. **Despite extensive land** reforms, collectivisation, the **Great Leap Forward and** other initiatives, the per capita grain output in 1978 was the same as it was in the mid-1950s.

उन्होंने महसूस किया कि विकेंद्रीकरण. आत्मनिर्भरता. विदेश प्रौद्योगिकी और उत्पादों तथा पूंजी के बहिष्कार पर आधारित आर्थिक विकास माओवादी दुष्टिकोण से विफल रहा है। व्यापक भूमि सुधारों, सामुदायिकीकरण और ग्रेट लीप फॉरवर्ड तथा अन्य पहलों के बाद भी 1978 में प्रतिव्यक्ति अन्न उत्पादन उतना ही था, जितना 1950 के दशक के मध्य में था।

It was found that establishment of infrastructure in the areas of education and health, land reforms, long existence of decentralised planning and existence of small enterprises had helped positively in improving the social and income indicators in the post reform period. Before the introduction of reforms, there had already been massive extension of basic health services in rural areas.

यह भी देखा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आधारिक संरचना की स्थापना किये जाने के फलस्वरूप भूमि सुधारों, दीर्घकालिक विकेंद्रीकृत योजनाओं और लघु उद्योगों से सुधारोत्तर अवधि में सामाजिक और आय संकेतकों में निश्चित रूप से सुधार हुआ था। सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर प्रसार हो चुका था।

The experimentation under decentralised government enabled to assess the economic, social and political costs of success or failure.

Scholars argue that in Pakistan the reform process led to worsening of all the economic indicators. We have seen in an earlier section that compared to 1980s, the growth rate of GDP and its sectoral constituents have fallen in the 1990s.

विकेंद्रीकृत शासन के प्रयोग के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लागतों की सफलता या विफलता का आकलन किया जा सका।

विद्वान तर्क देते हैं कि सुधार प्रक्रिया से पाकिस्तान में तो सभी आर्थिक संकेतकों में गिरावट आयी है। हमने पिछले खंड में देखा है कि वहां 1980 को दशक की तुलना में जी. डीपी. और क्षेत्रक घटकों की संवृद्धि दर 1990 के दशक में कम हो गई है।

Though the data on international poverty line for Pakistan is quite healthy, scholars using the official data of Pakistan indicate rising poverty there. The proportion of poor in 1960s was more than 40 per cent which declined to 25 per cent in 1980s and started rising again in the recent decades.

यद्यपि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से संबंधित आँकड़े बहुत सकारात्मक रहे हैं, परंतु पाकिस्तान के सरकारी आँकडों का प्रयोग करने वाले यह संकेत देते हैं कि वहां निर्धनता बढ़ रही है। 1960 के दशक में निर्धनों का अनुपात 40 प्रतिशत था. जो 1980 के दशक में गिर कर 25 प्रतिशत हो गया और हाल के दशकों में पुन: बढ़ने लगा।

When there was a good harvest, the economy was in good condition, when it was not, the economic indicators showed stagnation or negative trends. You will recall that India had to borrow from the IMF and World Bank to set right its balance of payments crisis; foreign exchange is an essential component for any country and it is important to know how it can be earned

जब फसल अच्छी होती थी तो अर्थव्यवस्था भी ठीक रहती थी और फसल अच्छी नहीं होती थी तो आर्थिक संकेतक नकारात्मक प्रवृतियां दर्शाते थे। आपको ध्यान होगा कि भारत को अपने भुगतान संतुलन संकट को ठीक करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उधार लेना पड़ा था। विदेशी मुद्रा प्रत्येक देश के लिए एक अनिवार्य घटक है और यह जानना आवश्यक है कि इसे कैसे अर्जित किया जाता है।

If a country is able to build up its foreign exchange earnings by sustainable export of manufactured goods, it need not worry. In Pakistan most foreign exchange earnings came from remittances from Pakistani workers in the Middle-east and the exports of highly volatile agricultural products; there was also growing dependence on foreign loans on the one hand and increasing difficulty in paying back the loans on the other.

यदि कोई देश अपने विनिर्मित उत्पादों के धारणीय निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने में समर्थ है, तो उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में अधिकांश विदेशी मुद्रा मध्यपूर्व में काम करने वाले पाकिस्तानी श्रमिकों की आय प्रेषण तथा अति अस्थिर कृषि उत्पादों के नियातों से प्राप्त होती है। एक ओर विदेशी ऋणों पर निर्भर रहने की प्रवृति बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर पुराने ऋणों को चुकाने में कठिनाई बढ़ती जा रही थी।

CONCLUSION

What are we learning from the developmental experiences of our neighbours? India, China and Pakistan have travelled about seven decades of developmental path with varied results. Till the late 1970s, all of them were maintaining the same level of low development. The last three decades have taken these countries to different levels. India, with democratic institutions, performed moderately, but majority of its people still depend agriculture. Infrastructure is lacking in many parts of the country.

निष्कर्ष

अपने पड़ोसी देशों के विकास अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है? भारत. पाकिस्तान और चीन की लगभग सात दशकों से लंबी विकास यात्रा रही है और उनको अलग-अलग परिणाम प्राप्त हुए हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में तीनों का ही विकास स्तर निम्न था। पिछले तीन दशकों में इन तीनों देशों का विकास स्तर अलग-अलग रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं सहित भारत का निष्पादन साधारण रहा है। अधिकतर लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। भारत के अनेक भागों में आधारिक संरचना का अभाव है।

It is yet to raise the level of living of more than onefourth of its population that lives below the poverty line. Scholars are of the opinion that political instability, overdependence on remittances and foreign aid along with volatile performance of agriculture sector are the reasons for the slowdown of the Pakistan economy

भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले एक चौथाई से भी अधिक जनसंख्या का रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। विद्वानों का मत है कि राजनैतिक अस्थिरता. प्रेषणों और विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और कृषि क्षेत्रक का अस्थिर निष्पादन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गिरावट के कारण हैं। रहा है।

Yet, last three years, many macroeconomic indicators began showing positive and higher growth rates reflecting the economic recovery. In China, the lack of political freedom and its implications for human rights are major concerns; yet, in the last four decades, it used the 'market system without losing political commitment' and succeeded in raising the level of growth alongwith alleviation of poverty.

पिछले तीन वर्षो में. कई समष्टि अर्थशास्त्र सूचक सकारात्मक ऊंची विकास दर दर्शा रहे हैं, जो आर्थिक पुनरुत्थान को सूचित कर रहे हैं। चीन में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव तथा मानव अधिकारों पर उसके निहतार्थ चिंता के मूल विषय हैं। फिर भी. अंतिम चार दशकों में से इसने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खोये बिना, बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया तथा निर्धनता निवारण के साथ-साथ संवृद्धि के स्तर को बढाने में सफल रहा है।

China has ensured social security in rural areas. Public intervention in providing social infrastructure even prior to reforms has brought about positive results in human development indicators in China.

सामुदायिक भू-स्वामित्व को कायम रखते हुए और लोगों को भूमि पर कृषि की अनुमति देकर चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। चीन में सुधारों से पूर्व ही सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराने में सरकारी हस्तक्षेप द्वारा मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम हुए हैं।